भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं.1369

(जिसका उत्तर सोमवार 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों का प्रभाव

1369. **श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के कच्चे तेल के आयात बिल पर पश्चिम एशिया में हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के राजकोषीय और व्यापक आर्थिक प्रभावों का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत के कच्चे तेल के आयात बिल पर चालू खाता शेष और राजकोषीय स्थिति संबंधी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के परिदृश्यों के अनुमानित प्रभाव क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति, ईंधन सब्सिडी और विकास अनुमानों पर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक रहने वाली अस्थिरता के संभावित प्रभाव की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति सबसे संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रक कौन-से हैं और उत्पादन तथा संभारतंत्र लागत पर इसके प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन क्या है; और

(ङ) व्यापक आर्थिक स्थिरता की रक्षा करने, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक ऊर्जा बाजार में व्यवधानों के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या आकस्मिक उपाय प्रस्तावित किए गए है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क)-(ग): पश्चिम एशिया में हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों ने कच्चे तेल का आयात करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर प्रमुख प्रभाव के साथ वैश्विक रूप से देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जून 2026) के अनुसार, पश्चिम एशिया में हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे पूर्व में तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव के दौरान हुए अनुभव के समान चालू खाता घाटा पर प्रभाव के साथ कच्चे तेल का आयात बिल बढ़ गया है। तथापि, भारतीय कच्चे तेल की औसत बास्केट कीमतें अप्रैल 2026 में 114.5 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से काफी कम होकर जुलाई 2026 (22 जुलाई तक) में 77.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ-साथ सेवाओं के निर्यात और प्रेषण प्राप्तियों में निरंतर वृद्धि से बाह्य क्षेत्र को सहायता मिलने और चालू खाते पर दबाव कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित उपायों से पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलने और भारत की विदेशी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

हालांकि वैश्विक अनिश्चितताएं काफी अधिक बनी हुई हैं, वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही हेतु उच्च-आवृत्ति संकेतक आर्थिक गतिविधि और घरेलू मांग में निरंतर गति की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा, अप्रैल-जून 2026 के दौरान औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 3.9 प्रतिशत पर सामान्य बनी हुई है, जो मूल्य स्थिरता को दर्शाती है। इन रुझानों के अनुरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.6 प्रतिशत और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी नोट किया है कि वैश्विक वस्तु मूल्य उतार-चढ़ाव और लंबे समय तक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान विकास और मुद्रास्फीति परिदृश्य के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं।

राजकोषीय स्तर पर, सरकार ने उभरती स्थिति के बीच वृहद आर्थिक स्थिरता और समुत्थानशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल राजकोषीय रणनीति अपनाई है। सरकार ईंधन सब्सिडी और राजस्व संग्रहण सहित राजकोषीय स्थिति पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रभावों का आकलन करना जारी रखे हुए है और राजकोषीय स्तर को बनाए रखने के लिए पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और चुनिंदा आयातों पर सीमा शुल्कों में अंशाकित संशोधन सहित उपयुक्त राजकोषीय उपाय किए हैं। आर्थिक स्थिरीकरण कोष सहित राजकोषीय बफर की उपलब्धता, राजकोषीय समेकन पथ को बनाए रखते हुए बाह्य उतार-चढ़ावों का जबाव देने के लिए अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करता है।

(घ) हाल के महीनों में ऊर्जा मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रभाव पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक और मध्यवर्ती उत्पादों की कीमतों और प्लास्टिक, पैकेजिंग, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, ऑटोमोटिव घटकों और अन्य विनिर्माण उद्योगों सहित संबंधित डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों पर पड़ा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि से घरेलू उत्पादक कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव पड़ा है, जिससे थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति मार्च 2026 में 4.0 प्रतिशत से बढ़कर जून 2026 में 9.9 प्रतिशत हो गई है। तथापि, इस अवधि के दौरान औद्योगिक गतिविधि समुत्थानशील बनी हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि मार्च 2026 में 3.0 प्रतिशत से बढ़कर मई 2026 में 5.1 प्रतिशत हो गई, जबकि नौ प्रमुख उद्योगों में वृद्धि भी मार्च 2026 में 2.9 प्रतिशत से बढ़कर जून 2026 में 5.0 प्रतिशत हो गई, जो उच्च इनपुट और लॉजिस्टिक्स लागत के बावजूद औद्योगिक गतिविधि में निरंतर गति को दर्शाती है।

(ङ) सरकार ने ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण औद्योगिक इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करने, इनपुट लागत दबावों को कम करने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने, औद्योगिक कार्यकलापों को सहायता देने और वृहद आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए हैं। चुनिंदा पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक पर अस्थायी सीमा शुल्क छूट प्रदान की गई थी। इसके अलावा, व्यवसायों को सहायता करने के लिए भारत समुद्री बीमा पूल रिलीफ (निर्यात सुविधा के लिए समुत्थानशील और लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप) योजना शुरू की गई थी। उच्च माल ढुलाई, बीमा और युद्ध-जोखिम लागतों को कम करने के लिए आरओडीटीईपी (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) लाभों को बहाल किया गया था। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 के माध्यम से नकदी सहायता भी प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, सरकार मुक्त व्यापार करारों और व्यापक आर्थिक भागीदारी/सहयोग करारों के अपने नेटवर्क का विस्तार करके व्यापार समुत्थानशीलता को सुदृढ़ कर रही है।

इसके अतिरिक्त, कच्चे तेल के आयात स्त्रोतों के विविधीकरण, रणनीतिक साझेदारियों का विस्तार, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की वृद्धि, वैकल्पिक ईंधनों का संवर्धन, महत्वपूर्ण ऊर्जा इनपुट का घरेलू उत्पादन और कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण स्कीम के कार्यान्वयन जैसी विविध रणनीतियों के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है। ऊर्जा के उपयोग को इष्टतम करने के लिए एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहन करने जैसी मांग-पक्ष पहल भी की गई है।

सरकार ने सुनिश्चित गैस आपूर्ति, आयात स्रोतों के विविधीकरण, अग्रिम खरीद और बफर स्टॉक के रखरखाव के माध्यम से उर्वरकों और अन्य आवश्यक कृषि इनपुट की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। इन प्रयासों को विदेशी क्षेत्र समुत्थानशीलता को सुदृढ़ करने और विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचे के उदारीकरण, विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के उपायों, विशेष स्वैप सुविधाओं और भागीदार देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान को बढ़ावा देने के माध्यम से विदेशी मुद्रा अंतर्वाह को सहायता देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पहलों द्वारा बढ़ाया गया है। साथ ही, ये समन्वित उपाय भारत की वृहद आर्थिक स्थिरता को मजबूत करते हैं, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक ऊर्जा बाजार में व्यवधानों के प्रभाव को कम करते हैं।

*****